

पटना उच्च न्यायालय

विशेष पीठ में

दिवानी संदर्भ 4/1952

निर्णय दिनांक 01.12.1953

याचिकाकर्ताओं: इन कानूनी मामलों में: बद्री नारायण लाल

कानून व्यवसायी अधिनियम, 1879 - धारा 14

शाहाबाद के जिला न्यायाधीश द्वारा कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश भेजा गया जिसमें एक वकील को वकालत से निलंबन की सिफारिश की गयी।

सभी तीन न्यायाधीशों ने अपने अलग-अलग निर्णयों में निर्देश को असक्षम पाया।

यह निर्णित किया गया कि मुंसीफ कोर्ट में कथित दुर्यवहार किया गया था, इसलिये मुंसिफ ही निर्देश के लिये सक्षम अधिकारी था, न की जिला न्यायाधीश, अतः निर्देश को खारीज कर दिया गया।

[पारा 6, 7, 12 and 13]

पटना उच्च न्यायालय**विशेष पीठ में**

दिवानी संदर्भ 4/1952

निर्णय दिनांक 01.12.1953

याचिकाकर्ताओं: इन कानूनी मामलों में: बट्टी नारायण लाल

माननीय न्यायाधीशगण/कोरम:

दास, जुगल किशोर नारायण और जमुआर, न्यायाधीशगण

वकील:

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिए: सरकारी अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिए: ए.बी.एन. सिन्हा, अधिवक्ता

निर्णय**जुगल किशोर नारायण, न्यायाधीश**

1. यह शाहाबाद के जिला न्यायाधीश द्वारा कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक निर्देश है, जिसमें सिफारिश की गई है कि बक्सर में वकालत करने वाले श्री बट्टी नारायण लाल को तीन साल की अवधि के लिए वकालत से निलंबित कर दिया जाए।

2. कार्यवाही को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया जा सकता है। बक्सर के दूसरे मुन्सिफ की अदालत में लंबित 1949 के निष्पादन मामले संख्या 373 में डिक्री धारक छत्रधारी दुबे ने नवंबर, 1951 में उस किश्त राशि को वापस लेने के लिए आवेदन किया, जिसे उक्त निष्पादन मामले में निर्णय-देनदार द्वारा जमा किया गया था। निकासी के लिए याचिका वकील श्री बट्टी नारायण लाल के माध्यम से दायर की गई थी और

28-11-1951 को राशि वापस ले ली गई थी। 25-3-1952 को, छत्रधारी दुबे ने मुन्सिफ के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि वकील ने, हालांकि उसने 1,133/8 रुपये निकाल लिये, लेकिन याचिकाकर्ता/डिक्रीदार थे ने उसे राशि का भुगतान नहीं किया था, और नहीं वह इसका भुगतान करने के लिए इच्छुक नहीं था। यह याचिका 27-3-1952 पर कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन के रूप में दर्ज की गई थी, और मुन्सिफ ने निर्देश दिया कि विरोधी पक्ष को 10-4-1952 तक कारण दिखाने के लिए सूचना जारी किया जाए, कि उसके आचरण की सूचना इस अदालत को आवश्यक कार्रवाई के लिए क्यों नहीं दी जानी चाहिए। नोटिस 21-4-1952 द्वारा दिया गया था, जिस तारीख को वकील पेश हुआ और समय के लिए याचिका दायर की।

3-5-1952 को आवेदक छत्रधारी दुबे ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि उन्हें 1,133/8 रु- विरोधी पक्ष से प्राप्त किया, और इसलिए वह अपना आवेदन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। यह याचिका विद्वान मुन्सिफ के सामने 5-5-1952 पर रखी गई थी, और क्योंकि इसमें राजस्व टिकट नहीं था, इसलिए इसमें एक राजस्व टिकट लगाने की अनुमति दी गई थी। 10.05.1952 को, जो अगली तारीख तय की गई थी, न तो आवेदक और न ही विरोधी पक्ष उपस्थित हुआ, और विद्वान मुन्सिफ ने तथ्यों को बताने के बाद यह राय व्यक्त की कि वकील, जिसने डिक्री धारक को राशि का भुगतान नहीं किया था, "अस्थायी गबन" का दोषी था। इसके बाद उन्होंने मामले का रिकॉर्ड आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला न्यायाधीश को भेज दिया।

जिला न्यायाधीश ने मामले को खुद के निष्पादन के लिये लिया और वकील को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया कि इस मामले की सूचना उच्च न्यायालय को क्यों नहीं दी जानी चाहिए। 17-6-1962 को कारण दिखाया गया था, और 14-7-1952 को, जिला न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया कि वह बक्सर में

26-7-1952 को इस मामले की सुनवाई करेंगे, जहाँ वे आपराधिक न्यायालयों का निरीक्षण करेंगे। हालाँकि विद्वान जिला न्यायाधीश ने तारीख के रूप में 26-7-1952 निर्धारित किया था, उन्होंने 25-7-1952 को बक्सर में मामले को उठाया, जिस तारीख को उन्होंने बक्सर बार के एक प्रमुख वकील छत्रधारी दुबे और बाबू बब्बनजी लाल से पूछताछ की, और 05.08.1952 को उन्होंने यह रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई कि वकील को तीन साल की अवधि के लिए वकालत से निलंबित कर दिया जाए।

3. श्री ए. बी. एन. सिन्हा, जो अधिवक्ता के लिए हमारे सामने पेश हुए हैं, ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि हालांकि मामले की सुनवाई 26.07-14.09.52 को पर होनी थी, लेकिन जिला न्यायाधीश ने 15.07.1952 को गवाहों से पूछताछ की, और यह कि दो गवाहों, छत्रधारी दुबे और बाबू बब्बनजी लाल से पूछताछ करने के बाद, उन्होंने श्री बद्री नारायण लाल को अपने स्वयं के गवाहों से पूछताछ करने का कोई मौका नहीं दिया। आदेश-पत्र में यह भी नहीं दिखाया गया है कि किसी भी तर्क को सुना गया था। विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया है कि चूंकि पीठासीन अधिकारी, यानी बक्सर के मुन्सिफ द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए जिला न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय को भेजा गया निर्देश अक्षम है, और उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का विद्वान वकील द्वारा आश्रय किया गया है है, और वे निर्णय हैं-- 'माउंट। जनक किशोर ए. आई. आर. 1916 पैट 115 (ए) के मामले में;-- 'सम्राट बनाम सत्येंद्र नाथ' ए. आई. आर. 1920 पैट 274 (बी) और-- 'मुख्तार मंजूरुल हक बनाम राजा सम्राट' मनु/बी. एच./0273/1922:ए. आई. आर. 1923 पैट 185 (1) (एस. बी.) (सी)। पहले मामले में, न्यायाधीश मलिक ने बताया कि कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 की शर्तें यह अनिवार्य बनाती हैं कि जांच न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, और न्यायाधीश एटकिंसन ने कहा कि धारा 14 एक प्रक्रिया प्रदान करती है

जिसका पालन किया जाना चाहिए, और उस व्यक्ति को नामित करती है जिसे जांच करनी चाहिए और आरोप लगाना चाहिए। दूसरे मामले में, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा में विचार किया गया है कि जांच उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए जिसमें कदाचार या अपराध होने का आरोप है। यह मामला और मामला-- 'मनु/बी/एच/0063/1922:ए. आई. आर. 1923 पैट 185 (1) (एस. बी.) (सी)', के मामले में इस न्यायालय के विशेष पीठ के निर्णय हैं, और वे एक ही प्रभाव के हैं।

ये निर्णय, निस्संदेह, हमारे समक्ष श्री सिन्हा के तर्क का समर्थन करते हैं; लेकिन विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इन मामलों का गलत निर्णय लिया गया था, और उन्होंने 'ए, एक मुख्तार' में दर्ज मामलों का हवाला दिया है: मनु/बी/एच/0208/1937: ए आई आर 1938 पैट 17 (एस बी)(डी) इस कानूनी मामले में रविन्द्र चन्द्र चटर्जी मन/डब्लू बी/0384/1922: ए आई आर 1922 कैल 484 (ई) एवं इस कानूनी मामलों में बेसुगोपाल नायडू मनु/टी एन/0758/1915: ए आई आर 1926 मद 1044 (सी) मनु/बी एच/0208/1937 ए आई आर 1938 पैट (एस बी) (डी) में निर्णय, .ए. आई. आर. 1926 मैड 1044 (पी)। निर्णय-- 'MANU/BH/0208/1937:ए. आई. आर. 1938 पैट 17 (एस. बी.) (डी.) भी एक विशेष पीठ का निर्णय है; लेकिन इस मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।

4. इस न्यायालय की एक और विशेष पीठ का निर्णय भी है-'इस कानूनी मामले में बनमाली दास' मनु/बीएच/0237/1922:ए. आई. आर. 1922 पैट 603 (2) (जी) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब एक मुन्सिफ, जिसके न्यायालय में एक वकील ने एक पक्ष की ओर से लिखित बयान दायर किया था, बिना निर्देश और ऐसा करने के लिए अधिकृत किए, ने कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, तो जिला न्यायाधीश को मामले को उच्च न्यायालय में भेजने का कोई अधिकार नहीं था,

क्योंकि धारा 14 के तहत यह केवल उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को जिसके न्यायालय अपराध किया गया था, जिनके पास निर्देश भेजने की शक्ति थी। दुर्भाग्य से, इन फैसलों का उल्लेख विशेष पीठ के फैसले में नहीं किया गया है-- 'मनु/बीएच/0208/1937:ए. आई. आर. 1938 पैट 17 (एस. बी.) (डी) '। 'ए. आई. आर. 1922 कैल 434 (ई)' में रिपोर्ट किए गए कलकत्ता मामले को विशेष पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ भेजा गया था-'एम. ए. एन. यू./बी. एच./0208/1937:ए. आई. आर. 1938 पैट 17 (एस. बी.) (डी.) और कलकत्ता का यह निर्णय, निस्संदेह, इस विचार का समर्थन करता है कि जिला न्यायाधीश अपने समक्ष वकालत करने वाले एक वकील के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है, भले ही अपराध उसके अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में किया गया हो।

5. इन फैसलों के अलावा, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने मद्रास मामले का उल्लेख किया है-- 'मनु/टी. एन./0758/1925:ए. आई. आर. 1926 मैड 1044 (पी) ', जिसमें ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट रूप से असहमति जताई गई है। इस मद्रास मामले में, उनके न्यायाधीशों ने कहा है कि कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 उस आरोप पर विचार करने को उस न्यायालय तक सीमित नहीं करता है जिसमें दुर्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है, ऐसा व्याख्या का मतलब है कि, धारा 14 में कुछ ऐसा पढ़ना है जो वहां नहीं है। मेरी राय में, भले ही इस निर्णय का पालन किया जाए, हम इस विशेष मामले में यह नहीं मान पाएंगे कि जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश सक्षम है। जिला न्यायाधीश ने अपने समक्ष किए गए किसी भी दुर्यवहार के संबंध में इस मामले में कार्यवाही शुरू नहीं की। इस प्रस्ताव के लिए जगह नहीं है कि मुन्सिफ आरोप तैयार कर सकता है और एक निश्चित चरण तक मामले से निपट सकता है जबकि, प्रतिवेदन जिला न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत की जा सकती है। यहां तक कि मद्रास मामले के निर्णय पर, जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को सक्षम नहीं माना जा सकता है। इस मामले में स्थिति एक विचित्र है, क्योंकि जब मुन्सिफ ने कार्यवाही शुरू की थी, तब इस

न्यायालय को प्रतिवेदन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत की जानी थी। उद्धृत अधिकारियों में से कोई भी इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर सकता है, और इसलिए, न्यायिक राय के टकराव को हल करने का कोई प्रयास किए बिना, अभासी या वास्तविक इस मामले में, निर्देश को पूरी तरह से असक्षम के रूप में अस्वीकार कर सकते हैं।

हम धारा 14 में निहित काफी विस्तृत प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, और यह स्पष्ट है कि इन प्रावधानों का इस मामले में मुन्सिफ द्वारा पालन नहीं किया गया था। यह मुन्सिफ है जिसकी अदालत में निष्पादन का मामला लंबित था जिसमें पैसा जमा किया गया था, और यह मुन्सिफ है जिसके सामने शिकायत की गई थी। मुन्सिफ ने संज्ञान लिया, और बिना कोई सबूत लिए, एक निष्कर्ष दर्ज किया और अभिलेख को जिला न्यायाधीश को भेजा, जिन्होंने कुछ और जांच की और मामले को उच्च न्यायालय को सूचित किया। धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, रिपोर्ट को जिला न्यायाधीश के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था, अंत में, धारा 14 के अंतिम कंडिका के अनुसार, प्रतिवेदन के साथ जिला न्यायाधीश की राय भी होनी थी। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस संदर्भ को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मुन्सिफ द्वारा कोई पूर्ण जांच नहीं की गई थी।

प्लीडर के विद्वान वकील ने हमारे सामने वह लाइसेंस प्रस्तुत किया है जिसके तहत प्लीडर प्रैक्टिस कर रहा है और यह लाइसेंस दिनांकित 13-5-1953 है। प्लीडर को केवल मुन्सिफ अदालतों में वकालत करने का लाइसेंस मिला है और हमें आश्वासन दिया गया है कि पिछले लाइसेंस भी इसी तरह के थे। यदि यह स्थिति है, तो विद्वान जिला न्यायाधीश केवल इसलिए मामले से नहीं निपट सकता था क्योंकि वह जिले का न्यायिक प्रमुख था या इसलिए कि मुन्सिफ उसका अधीनस्थ था। वकील को उसके सामने वकालत करने वाला नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए, उसके पास कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई

कार्यवाही करने या कोई जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हर दृष्टिकोण से, श्री सिन्हा द्वारा किया गया तर्क सफल होना चाहिए, और निर्देश को खारिज किया जाना चाहिए।

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून के तहत हम खुद जांच कर सकते हैं और दोषी पाए जाने पर वकील को निलंबित या बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें हमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले के तथ्य कुछ अजीब हैं। वादी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, पैसे निकाल लिए थे; लेकिन उसने कहा था कि पैसे वास्तव में डिक्री धारक छत्रधारी दुबे की उपस्थिति में निकाले गए थे, और उसने खुद निकाले गए पैसे में से कुछ खर्च किया था। कहा जाता है कि 1951 के मनी सूट नंबर 201 में अदालत शुल्क खरीदने में 206/- रुपये खर्च किए गए थे, जिसे छत्रधारी दुबे ने बक्सर के प्रथम मुन्सिफ की अदालत में एक मनु राखन अहिर के खिलाफ दायर किया था। श्री बब्बनजी लाल वक्सर बार के एक काफी वरिष्ठ वकील ने इस मामले में कुछ रुचि ली, शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि इसमें बार की प्रतिष्ठा शामिल है; लेकिन, पक्षकारों, यानी छत्रधारी दुबे और वकील, श्री बद्री नारायण लाल के अभ्यावेदन को सुनने के बाद भी, वे यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि यह वास्तव में गबन या अस्थायी गबन का मामला था। वकील के खिलाफ छत्रधारी दुबे द्वारा की गई शिकायत ने वकील की ओर से एक गंभीर आपराधिक अपराध का खुलासा किया; लेकिन, हालांकि छत्रधारी दुबे ने साहसपूर्वक कहा था कि वकील ने डिक्री की राशि 1,133/8- योग का का दुरुपयोग किया था एवं उन्होंने प्लीडर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया।

जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ए. आई. आर. 1920 कैल 565 (एच) के मामले में 'चंडी चरण मित्र', एक वकील में बताया था, हालांकि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में आपराधिक दुराचार के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दोषसिद्धि

का आदेश दिया जाना चाहिए, विवर्जन के आदेश के पूर्व यह सामान्य नियम होना चाहिए जहां कथित कदाचार का अदालत के साथ उसके व्यावहारिक और तत्काल संबंध में एक वकील के आचरण से कोई सीधा संबंध नहीं है। मैं मुखर्जी, ए. सी. जे. से सम्मानपूर्वक सहमत हूं कि प्रत्येक मामले में लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति वास्तव में एक गंभीर आपराधिक आरोप की जांच के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाने से पूर्वाग्रहित होगा, निस्संदेह, यदि वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को मंजूरी दी जाती है, तो परिणाम वादी के लिए एक स्पष्ट अन्याय हो सकता है। कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत एक कार्यवाही, आखिरकार, एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें वादी को वही लाभ नहीं होगा जो उसे आपराधिक न्यायालय में नियमित परीक्षण होने पर उपलब्ध होगा।

7. इस न्यायालय की एक विशेष पीठ ने 'बारगढ़ के मुख्तार' मनु/बी. एच./0057/1942 कहा: ए. आई. आर. 1943 पैट 52 (आई) में कहा गया है कि जहां एक कानूनी व्यवसायी के खिलाफ लाया गया आरोप एक गंभीर अपराध के आरोप के बराबर है, वहां उस अपराध के लिए अभियोजन शुरू करना और यदि कोई दोषसिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना उचित प्रक्रिया है। हैरिस, सी. जे., जिन्होंने इस न्यायालय का निर्णय दिया, ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की: कि "यह याद रखना चाहिए कि यदि कोई अभियोजन शुरू किया जाता है तो अपील के अधिकार के साथ एक पूर्ण परीक्षण होता है, जबकि कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत कार्यवाही एक संक्षिप्त चरित्र की होती है। जहाँ गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, वहाँ अभियुक्त मुख्तार को पूर्ण सुनवाई और उसके अपील करने के अधिकार से वंचित करना गलत होगा। मेरे निर्णय में, हमें वर्तमान मामले में इन निर्णयों का पालन करना चाहिए (उनके प्रभुत्व में यह बताया गया है कि कई मामलों में यह दृष्टिकोण लिया गया था) और यह मानना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई आपराधिक न्यायालयों में की जानी चाहिए और परिणाम में या दोषसिद्धि

स्थिति में इस मामले को इस न्यायालय द्वारा कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत निपटा जा सकता है।

इस कारण से भी, वर्तमान निर्देश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और हम इस न्यायालय में इस वर्तमान मामले को ऐसा नहीं मान सकते हैं जिसमें हमें स्वयं एक अलग कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

8. इसलिए परिणामस्वरूप, मैं इस निर्देश का को उन्मुक्त करूँगा।

दास न्यायाधीश

9. मैं अपने विद्वान भाई से सहमत हूँ कि निर्देश को खारिज कर दिया जाना चाहिए, और हमें वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, मुझे यह कहना होगा कि 'मनु/बी. एच./0063/1922' ए आई आर 1923 पेट 185 (1) (एस बी/(सी) मनु/बी. एच./0063/1922 में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के बीच एक स्पष्ट संघर्ष है। एच./0208/1937 (डी.)' में व्यक्त किया गया है। शायद, उपरोक्त दो निर्णयों द्वारा प्रकट किए गए विचारों के टकराव को हल किया जा सकता है; लेकिन वर्तमान मामले में कुछ भी उस संघर्ष पर नहीं बदलता है, और अगर और जब भविष्य में कोई अवसर उत्पन्न होता है तो ऊपर उल्लिखित दो निर्णयों के बीच स्पष्ट संघर्ष के संबंध में अंततः खुद को व्यक्त करने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैंने निर्दिष्ट दो निर्णयों में व्यक्त किए गए एक या दूसरे दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में अपनी अंतिम राय व्यक्त की है।

10. वर्तमान मामले को, मेरी राय में, दो बहुत ही छोटे आधारों पर निपटाया जा सकता है। अधिवक्ताओं के द्वारा तर्क दिया गया है कि संबंधित वकील को केवल बक्सर में मुन्सिफों के न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार था। उस कथन के समर्थन में एक लाइसेंस

प्रस्तुत किया गया है। कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के बारे में कोई भी जो भी विचार रखता है, जिला न्यायाधीश वकील के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता था, अगर वकील को न तो अपने न्यायालय में वकालत करने का अधिकार था और न ही वह वास्तव में शाहाबाद के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वकालत करता था। वास्तव में डिक्री धारक ने वादी के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मुन्सिफ को आवेदन दिया। चाहे वह आवेदन मुन्सिफ को उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में किया गया था जिसमें वकील ने वकालत की थी या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में उस कार्यवाही के संबंध में किया गया था जिसके न्यायालय में कथित कदाचार किया गया था, यह मुन्सिफ का कर्तव्य था कि वह कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के पहले भाग द्वारा अनुध्यात जांच करे। मुन्सिफ ने ऐसी कोई जांच नहीं की, जैसा कि धारा 14 में विचार किया गया है। शाहाबाद के जिला न्यायाधीश धारा 14 के दूसरे भाग के तहत आए, जिसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ सिविल न्यायाधीश द्वारा बनाई गई रिपोर्ट ऐसे न्यायाधीश के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिला न्यायाधीश के न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। जिला न्यायाधीश ने, निस्संदेह, एक या दो गवाहों से पूछताछ की; लेकिन उन्होंने कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत विचार के अनुसार जांच भी नहीं की। इस मामले में जिला न्यायाधीश दो कारणों से जांच करने के लिए सक्षम नहीं था: पहला, संबंधित प्लीडर को जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वकालत करने का कोई अधिकार नहीं था, और दूसरा, प्लीडर के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला न्यायाधीश को कोई आवेदन नहीं दिया गया था। यह स्थिति होने के नाते, कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया था, इस सवाल के बावजूद कि क्या विचार व्यक्त किया गया था-'मनु/बीएच/0063/1922:ए. आई. आर. 1923 पैट 185 (1) (एस. बी.) (सी) 'या व्यक्त विचार-' मनु/बी. एच./0208/1937:ए. आई. आर. 1938 पैट 17 (एस. बी.) (डी.)

'सही है। धारा 14, कानूनी व्यवसायी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है, निर्देश असक्षम है।

11. निर्देश को अस्वीकार करने के लिए मेरा दूसरा आधार यह है: डिक्री-धारक की ओर से आरोपित तथ्य, यदि सत्य हैं, तो एक बहुत ही गंभीर आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं, और इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि जब बार के किसी सदस्य के खिलाफ आरोपित तथ्य एक गंभीर आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं और तथ्यों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो यह उचित नहीं है कि कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत जांच की जानी चाहिए। हालाँकि इस मामले में कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन पूर्वाग्रह का सवाल प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि उन आरोपों के संबंध में संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत जांच की जाती है जो एक गंभीर आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं और जिसे वादी ने अस्वीकार करने का सबसे पहला अवसर लिया है, तो वादी बहुत पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। यह भी एक आधार है कि वर्तमान मामले में संदर्भ को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

12. उपरोक्त दो कारणों से, मैं अपने विद्वान भाई से सहमत हूँ कि निर्देश को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और हमें संबंधित वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इन दो कारणों को देखते हुए, वादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करना अनावश्यक है।

जमुआर, न्यायाधीश

13. कहा जाता है कि इस मामले में की गई जांच कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। मैं सहमत हूँ कि इस संदर्भ का निर्वहन किया जाना चाहिए। प्लीडर पर एक निश्चित अपराध करने का आरोप है। यदि यह अपराध किया जाता है, तो

यह एक गंभीर आपराधिक अपराध था, और मेरी राय में, इस मामले की विशेष परिस्थितियों में, इसकी जांच कानूनी व्यवसायी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया में नहीं की जानी चाहिए थी।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।